हर जिले में स्थापित होंगी एक हजार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां : केशव

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) के तहत हर जिले में एक हजार इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया कि पीएम एफएमई योजना के तहत 15 हजार से अधिक इकाइयों को अनुदान दिया गया है। इनके माध्यम से 1.50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के तहत पांच हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ था। अब उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 लाई गई है। इससे प्रदेश में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने जा रहा है।

निवेश पोर्टल के माध्यम से अब तक 880 आनलाइन आवेदन आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने जिले में इकाइयों की स्थापना के लिए कम से कम एक हजार आवेदन कराने को कहा

संवाददाताओं को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ● जागरण

- **उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए इकाइयां स्थापित कराने के निर्देश**
- **इन्क्यूबेशन सेंटर के संचालन में महिला समूहों को दी जाएगी प्राथमिकता**

गया है। इन आवेदनों पर बैंकों से अनुदान दिलाने का भी अधिकारी प्रयास करेंगे। इसके लिए हर जिले में एक रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाएगा। साथ ही पीएम एफएमई योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कामन इन्क्यूबेशन सेंटर्स के संचालन के लिए भी स्वयं सहायता महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विजय बहादुर द्विवेदी आदि अधिकारी उपस्थित थे।